

प्रेषक

टीकम सिंह पेंवार
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

संवा में

समस्त जिलाधिकारी
(हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषय :- बालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में जिला योजना के स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक जिला योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला योजना की स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) हेतु बालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपदवार निम्नलिखित विवरणानुसार कुल 527.36 लाख (रुपये पचास करोड़ सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्णय पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
01	02	03
01	नैनीताल	54.86
02	उधमसिंहनगर	43.00
03	अल्मोड़ा	23.50
04	पिथौरागढ़	10.00
05	बागेश्वर	18.00
06	चम्पावत	40.00
	योग कुमाऊ	209.36
07	देहरादून	40.50
08	पौड़ी	62.00
09	टिहरी	52.00
10	चमोली	46.00
11	उत्तरकाशी	72.86
12	रूढ़प्रयाग	44.64
13	हरिद्वार	0.00
	योग गढ़वाल	318.00
	कुल योग	527.36

2- जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार आहरण के पूर्व जनपदवार जिला नियोजन एवं अनुभ्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिषद एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जावेगा। परिषद से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते हैं।

4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

5- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर 30प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-87(1)/दस-97-17(4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्ज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्ज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इसका कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणनों में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया बालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनाएं रोफ न होने पर ही नये कार्यों पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

8- जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

9- स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है।

10- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल ईग्जिक्यूटिव नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो- उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11- स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुभ्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिषद के अन्तर्गत हो तथा जिला अनुभ्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिषद से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

13- रु0 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा रु0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एवं सख्खा विभाग के जनपद/मण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

14- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कमोनेन्ट प्लान- 91-ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलसुधारण योजनाओं के लिए अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अनुदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

15- यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 824/जि0यो0/रा0यो0अ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत की जा रहा है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पेंवार)
संयुक्त सचिव

पू0स0 ७४७/उन्नीस(2)/08-2(112पे0)/2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कैमाऊ, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (हरिद्वार को छोड़कर)।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग/बजट सेल, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त विकास आयुक्त गढ़वाल/कुनौज।
9. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान (हरिद्वार को छोड़कर)।
12. निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- ✓ 14. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तडागी)
उप सचिव